

सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत, 2 8 घायल

मनोहरथाना के पिपलोदी में आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया व पुलिस की गाड़ियाँ तोड़ीं

झालावाड़, 25 जुलाई (निंसे)। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है, और 28 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर है। शुक्रवार सुबह मनोहरथाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की इमारत ढह गई, जिसमें 35 बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल पहुँचाया।

मनोहरथाना हॉस्पिटल के अनुसार, 5 बच्चों की मौत मौके पर ही हो गई थी, और 2 बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे को लेकर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुःख जताया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, “इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारजनों के साथ हैं।”

प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया: “राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल में हुई दुर्घटना दुःखद और अत्यंत पीड़ादायक है। इस कठिन घड़ी

■ आठवीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि छत से छोटे पत्थर व रेत गिरने लगी. शिक्षकों को बताया तो उन्होंने डांट कर बैठा दिया और खुद बाहर बैठकर पोहे-जलेबी का नाश्ता करने लगे. तभी इमारत भरभरा कर गिर गई और 35 बच्चे दब गये।

■ आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक व घायल बच्चों के परिजनों को मुआवज़ा तथा भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही की माँग की। शिक्षा विभाग ने पाँच शिक्षकों को निलम्बित किया।

में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायल छात्रों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रशासन प्रभावित लोगों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रहा है।”

पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है, ग्रामीण सुबह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण कई रास्ते भी बंद किए गए। पिपलोदी गांव में मातम का माहौल है। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर अधिक समय नहीं रुके तथा पुलिस एवं स्थानीय लोगों ने ही मोर्चा संभाला।

गांव वालों ने बताया कि सुबह से बारिश हो रही थी। प्रार्थना का समय हुआ

तो क्लासों के बच्चों को स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा करने के बजाय कमरे में बैठा दिया गया, ताकि वे भीगें नहीं। इसके कुछ ही देर बाद छत गिर गई और 35 बच्चे दब गए। गांव वालों ने बताया कि इस स्कूल में कुल 7 क्लासरूम हैं। हादसे के दौरान स्कूल के क्लासरूम में 71 बच्चे थे। स्कूल में 2 टीचर भी मौजूद थे, लेकिन छत गिरने के वक्त बिल्डिंग से बाहर थे और सुरक्षित हैं। दुर्घटना के समय स्कूल में मौजूद आठवीं क्लास में पढ़ने वाली वर्षा ने बताया कि जब छत गिरी, उस समय वह भी क्लासरूम के अंदर बैठी हुई थी। उसने देखा कि छोटे-छोटे पत्थर और रेत छत से गिरने लगे। उसने स्कूल में

मौजूद शिक्षकों को बताया कि पत्थर गिर रहे हैं तो शिक्षकों ने डांट –फटकार कर अंदर बैठ जाने को कहा और शिक्षक बाहर बैठकर पोहे और जलेबी का नाश्ता करने लगे। इसी बीच इमारत भरभरा कर गिर गई और बच्चे दब गए।

आक्रोशित ग्रामीणों ने घटनास्थल के समीप मुख्यमार्ग के गुराड़ी चौराहे पर टायर जलाकर जाम लगा दिया तथा रास्ते पर विद्युत पोल डाल दिए और चौराहे पर ही धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोग एक करोड़ मुआवज़ा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि इस हादसे में जिन बच्चों की जान गई है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए मृतक बच्चों के परिजनों को 1 करोड़ और घायल बच्चों के परिजनों को 50 लाख का मुआवज़ा मिलना चाहिए। इसके अलावा, मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई। ग्रामीणों ने भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।

एक बार तो प्रदर्शनकारी अचानक उग्र हो गए और पुलिस की गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया, ड्राइवर गाड़ियां (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई परीक्षा पेपर लीक मामले की सुनवाई 28 जुलाई को

जयपुर, 25 जुलाई। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा- 2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई सोमवार 28 जुलाई को होगी।

सुनवाई के दौरान, शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले की “इन-कैमरा” सुनवाई की। इस दौरान केस से जुड़े वकीलों के

■ हाई कोर्ट में आरपीएससी सचिव से सवाल जवाब हुए।

अलावा अन्य किसी को अदालत कक्ष में रुकने की अनुमति नहीं दी गई। वहीं, अदालतों आदेश की पालना में आरपीएससी के सचिव पेश हुए। अदालत ने उनसे भर्ती को लेकर सवाल –जवाब किए।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में बौते कई दिनों से प्रकरण में सुनवाई चल रही है। मामले में याचिकाकर्ता कैलाश चन्द शर्मा व अन्य का कहना है कि भर्ती परीक्षा का पेपर व्यापक स्तर पर लीक हुआ है और कई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मानवाधिकार आयोग ने स्कूल भवन गिरने का प्रसंज्ञान लिया

जयपुर, 25 जुलाई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने झालावाड़ में सरकारी स्कूल भवन गिरने से मासूमों की मौत के मामले में प्रसंज्ञान लिया है। इसके साथ ही, आयोग ने झालावाड़ जिला मजिस्ट्रेट, शिक्षा निदेशक, एसपी और डीईओ को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने इन अधिकारियों को कहा है कि घायलों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा दिलाई जाए। इसके साथ ही,

■ आयोग ने दोषियों पर तुरंत कार्यवाही करने व पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने को कहा।

आयोग ने घटना के दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने, साथ ही पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने को कहा है। आयोग ने अधिकारियों से 7 अगस्त को प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के समक्ष पेश करने को कहा है। आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने ये आदेश प्रकरण की प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करते हुए दिए।

आयोग ने कहा कि स्कूलों की छतों पर गंदगी साफ नहीं होने से हर साल मानसून में यहां पानी भर जाता है, जिससे छत धीरे-धीरे जर्जर हो जाती है। यह बड़े दुःख की बात है कि स्कूल के भवनों का रखरखाव भी निश्चित समयवाधि में ठीक से नहीं किया जाता। इसी के चलते इस स्कूल में छत गिरने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव राज्यसभा में पेश नहीं होगा

हालांकि इस्तीफे से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था

■ समझा जाता है कि धनखड़ के इस कदम के बारे में सरकार को जानकारी नहीं थी, कहा जाता है कि संभवतया इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा।

■ सूत्रों के अनुसार, सत्तारूढ़ पार्टी ने मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर लिया था। भाजपा ने इस पर सर्व सम्मति बनाने क लिए विपक्षी दलों से भी से सम्पर्क किया था और कुछ विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे।

■ चर्चा है कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा और स्पीकर बिड़ला एक जाँच कमेटी बनाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही वे तय करेंगे कि महाभियोग की सिफारिश की जाए या नहीं।

से आगे बढ़ाया जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा स्वीकार किए गए विपक्ष समर्थित महाभियोग प्रस्ताव को अब खारिज कर दिया

जाएगा, क्योंकि इसे औपचारिक रूप से सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया था। सूत्रों के अनुसार, धनखड़ के इसी कदम से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नाराज हो गई थी और इसी वजह से धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था।

महाभियोग की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ाई जाये, ताकि विपक्ष को “भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम” का लाभ लेने से वंचित किया जा सके, इसके लिये बुधवार को सरकार ने एक मीटिंग की।

सूत्रों का कहना है कि भाजपा स्वयं को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दिखाने के मामले में (विपक्ष से) आगे दिखाना चाहती है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव, इस वर्ष बिहार में और अगले साल बंगाल व तमिलनाडु में, से पहले भ्रष्टाचार-विरोधी संदेश दिया जा सके।

सत्तारूढ़ पार्टी ने 21 जुलाई, सोमवार से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र से पहले ही महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर लिया था। भाजपा ने विपक्षी दलों से संपर्क भी साधा था, ताकि सर्वदलीय सहमति बन सके, और कुछ विपक्षी सांसदों ने सरकार के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिये थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने संसद परिसर में मार्च निकाला

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का विरोध करते हुए शुक्रवार को संसद भवन

■ इसमें मल्लिकार्जुन खड्गे, राहुल गांधी, प्रियंका साहित कई बड़े नेता शामिल हुए और इन्होंने बिहार मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ नारे लगाए।

परिसर में मार्च निकाला। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा से संसद भवन के ‘मकर द्वार’ तक मार्च निकाला। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता एवं (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जुलाई को रिलीज़ किया जाना था।

रिलीज़ से कुछ दिन पहले मौलाना मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, उन्होंने कहा कि यह फिल्म मुस्लिम समुदाय को बदनाम करती है। हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई, ताकि सरकार सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 6 के तहत अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग कर सके।

इस रोक को चुनौती देते हुए फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामला फिर से हाईकोर्ट

को सौंप दिया है। फिल्म निर्माता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने आगे कोई रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा: “सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऐसी रोक को हटाता रहा है। क्यों फिर से रोक लगे? (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना और आंध्र की विधानसभा सीटें बढ़ाने की याचिका खारिज की

इन राज्यों ने माँग की थी, कि कोर्ट केन्द्र सरकार को परिसीमन शुरू करने के लिए निर्देश दे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 25 जुलाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनाया। यह रिट याचिका प्रोफेसर (डॉ.) के. पुरुषोत्तम रेड्डी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केन्द्र को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की धारा 26 को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश

■ याचिकाकर्ता राज्यों का तर्क था कि केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन कराना तथा आंध्र व तेलंगाना को इससे बाहर रखना अविवेकपूर्ण, असंगत व संविधान विरुद्ध है।

■ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में परिसीमन के नियम अलग हैं, इसलिए जम्मू-कश्मीर के साथ आंध्र व तेलंगाना में परिसीमन नहीं करना केन्द्र सरकार का पक्षपात पूर्ण कदम नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में ही विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन करना, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को इससे बाहर रखना, असंगत तथा अविवेकपूर्ण वर्गीकरण है और इसलिये यह संविधान के विरुद्ध है।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से की गई

तुलना तथा भेदभाव की दलील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में परिसीमन से संबंधित प्रावधान अलग है, और इसलिए जम्मू-कश्मीर के लिए जारी परिसीमन अधिसूचना से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाहर रखना न तो मनमाना है और न ही भेदभावपूर्ण।

से संतुष्ट हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“पहले हाईकोर्ट जाइए, वहां बहस कीजिए और फिर ज़रूरत हो तो यहां आइए। अब फिल्म निर्माता कह रहे हैं कि वे संतुष्ट हैं और याचिका वापस लेना चाहते हैं, तो आप लोग भी हाईकोर्ट जाइए। हमारा समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?”

फिल्म की रिलीज़ के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं दायर की गई थीं। फिल्म निर्माता ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई गई थी और केन्द्र सरकार को इसकी पुन: समीक्षा करने के लिए कहा गया था।

बाद में सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को फिल्म की जांच करने की अनुमति दी। इसके तहत निपुक्त एक पैनल ने

■ ये परिवर्तन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोड्यूसर को पुनः हाई कोर्ट जाने के आदेश दिये।

■ पिक्चर की रिलीज़ के खिलाफ याचिका दायर करने वाले जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मदनी ने इस सशर्त रिलीज़ को भी चुनौती देने की बात कही है।

■ फिल्म में प्रोड्यूसर के अधिवक्ता ने पिक्चर के खिलाफ और आगे स्थगन आदेश देने का विरोध किया।

■ अधिवक्ता के अनुसार, मदनी सुपर सेंसर जैसे व्यवहार कर रहे हैं।

■ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कांत ने इस पर कटाक्ष किया कि प्रोड्यूसर को लाभ ही हो रहा है, मुकदमा चलते रहने से, उसकी पिक्चर को पब्लिसिटी ही मिल रही है।

कुछ संशोधन सुझाए, जिनके बाद सरकार ने रिलीज़ को मंजूरी दी।

फिल्म के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और कन्हैयालाल हत्या मामले के एक आरोपी मोहम्मद जावेद ने याचिकाएं दायर की थीं।

अब उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने की घोषणा की है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल (मदनी की ओर से) और मेनका गुरूखामी (जावेद की ओर से) ने कहा कि वे इसे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

‘उदयपुर फाइल्स’ को पहले 11

विचार बिन्दु

विजय गर्व और प्रतिष्ठा के साथ आती है पर यदि उसकी रक्षा पौरुष के साथ न की जाय तो अपमान का ज़हर पिला कर चली जाती है। –मुक्ता

देश व लोकतंत्र के हित में चुनाव आयोग केवल सक्रिय ही नहीं, किंतु निष्पक्ष भी हो और ऐसा दिखे भी

लगभग निम्न आशय की बात चुनाव आयोग के हवाले से प्रिंट, टीवी व सोशल मीडिया में घूम रही है :--
--
पर उठाए जा रहे बेबुनियादी सवालो से डरकर, चुनाव आयोग ऐसे लोगों के बहकावे में आकर --
1. मरे हुए मतदाताओं
2. स्थाई तौर से प्रवास के गए मतदाताओं
3. दो जगह वोट बनवा चुके मतदाताओं
4. फर्जी मतदाताओं
5. विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी बात डालने वाले लोगों को पहले बिहार में और फिर पूरे देश में, संविधान के विरुद्ध जाकर बात डालने की अनुमति दें???

चुनाव आयोग भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित एक शक्तियुक्त आयोग है जिस पर देश में निष्पक्ष चुनाव करने का बहुत बड़ा दायित्व है। राजनीतिक दलों को भी बिना बात उसकी गरिमा को बेवजह ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, यह बात तो सामान्य से सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी मानेगा।

किंतु उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि चुनाव आयोग भी पूर्ण निष्पक्षता से अपना दायित्व निभाए।

कौन इस से असहमत होगा कि मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों से हटे। यह रूटीन एक्सरसाइज चुनाव आयोग नियमित रूप से करता आया है, किसी ने प्रश्न उठाया क्या कि ऐसा नहीं किया जाए?? तो फिर यह प्रश्न ही क्यों??

इसी प्रकार जिन मतदाताओं का नाम दो जगह मतदाता सूचियों में है उनका नाम एक जगह से विलोपित होना चाहिए किन्तु ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह किस स्थान पर मतदान करना चाहता है?? क्या नहीं हो ऐसा?? जिन लोगों को रोजी-रोटी व सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए ग्रामीण व शहरी दोनों जगह रहना पडता है जैसे कि अल्पायुभोगी दिहाड़ी काम वाले लोग, किसान – मजदूर आदि। सामान्य बुद्धि तो कहती है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करते वक्त ऐसे चिन्हित लोगों को अवसर दें कि वे कहां के मतदाता रहना चाहते है? केवल बीएलओ के द्वारा भरे या भराये गए गणना पत्र के आधार पर नाम कागजात सरासर अन्याय होगा और चुनाव आयोग की साख भी कुछ तो कम होगी ही, चुनाव आयोग माने या न माने।

इसी प्रकार जिन मतदाताओं में स्थाई तौर पर पुराना निवास छोड़ कर नई जगह रहना शुरू कर दिया उनका नाम भी हटना चाहिए और मैं समझता हूं किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोधी नहीं किया है। किंतु ऐसे मामलों में पूर्णत: निष्पक्ष रूप से जांच तो होनी चाहिए कि यह तथ्य सही है या BLO की लापरवाही है या कहीं BLO या BLA की मिलीभगत तो नहीं है, किसी दूसरे पक्ष के वोटर्स का नाम कटवाने की???

हर चुनाव के बाद पोलिंग बुथ के बाहर ऐसे व्यक्ति शिकायत करते मिलते है कि पहले उसका नाम था अब नहीं, क्यों??

और अब आयोग के द्वारा, मतदाता सूचियों में से फर्जी व विदेशी मतदाताओं के हटाने की बात पर विचार करे। शायद ही कोई असहमत होगा कि फर्जी व विदेशी लोगों के नाम मतदाता सूचियों में से हटने चाहिए? प्रश्न यह है कि आयोग ने यह प्रश्न पूछा क्यों? सबसे पहले आयोग ही स्पष्ट करे कि फर्जी और विदेशी मतदाताओं की पहचान कैसे की? ऐसे लोगों की सूची जारी करे जिन्हें आयोग फर्जी या विदेशी मानता है और उसके आधार बताए।

ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में, निम्न कारणों से होना संभव है :--
- की निष्क्रियता, लापरवाही के कारण या फिर BLO और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की मिलीभगत हो। यह मिली भगत पहले संभव थी तो अब भी हो सकती है। बहुत से लोगों को झुटमूट मृत बताया जा सकता है, निवास छोड़कर अन्यत्र बसाना बताया जा सकता है।

इसलिए आयोग को आगामी एक माह में ऐसे समस्त लोगों जिन्हें मृत या निवास छोड़ गए बात रहे है, उनकी बुधवार सूची बुथ पर, पंचायतों में, पटवारियों के पास, तहसील कार्यालयों में व पॉलिटिकल पार्टियों को उपलब्ध करानी चाहिए ताकि जिन को आपत्ति हो वे आपत्तियां दर्ज कर सकें।

जो समाचार है उनके अनुसार, आयोग को ज्ञात हुआ है कि विदेशी व फर्जी मतदाताओं के वोट दूसरे लोग डालते है। यह तो अत्यंत ही गंभीर बात आयोग में बताई है। फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया ही संदेह के घेर में आ जाएगी?

अगर आयोग के हवाले से छपी खबर सही है तो फिर आयोग को पता है कि किन फर्जी व विदेशियों के वोट कौन डालता-डलवाता है???? फिर तो आयोग विस्तृत सूचनाएं देश के सामने आने दे।

चलते-चलते, आम आदमी की जिज्ञासा है कि कौन देश का नागरिक कोन विदेशी, इसकी पहचान कौन दफ्तर कौन अधिकारी करते हैं? नागरिक होने का प्रमाण पत्र लेना हो तो चुनाव कार्यालय में दरखास्त दें या अब जो वोटरलिस्ट जारी करेगा आयोग वही प्रमाण पर्याप्त होगा नागरिकता दिखाने के लिए। वैसे कानून जानने वाले लोग मानते है कि चुनाव आयोग को नागरिकता की जांच का अधिकार नहीं। अब यह सही है या नहीं यह तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार या चुनाव आयोग जाने।

यों ही, एक बात सुनते आए है कि न्याय हो यही पर्याप्त नहीं, न्याय होता दिखना भी चाहिए। एक न्यायाधिकारी के सामने मुकदमा पेश होने के बाद सभी पक्षकारों और उनके पैरवी कर्ताओं को सुना जाता है। फैसले में सारी बातें विस्तार से लिखी जाती है। जो भी कानून के बातें कही जाती है वे लिखी जाती है। इन सभी पर न्यायाधीकारी अपना मत व्यक्त कर फैसला देता है। इस से न्याय हुआ दिखता है। फैसला तो यों भी हो सकता है कि सब को सुनने के बाद यह मानता हूं कि यह यह बात सही है और यह आदेश दिया जाता है ----? नहीं? किंतु नहीं क्यों कि ऐसा करने से न्याय होता दिखता नहीं।

अल्पज्ञानि सामान्य आदमी का तो मानना है कि यह बात चुनाव आयोग भी लागू होती है। चुनाव आयोग कोई छोटे अधिकारियों का दफ्तर नहीं जहां कोई गलती कर दे तो ऊपर के दफ्तरों में जाने के रास्ते है। यदि चुनाव आयोग मतदाताओं का नाम बिना पूर्ण- विस्तृत जांच के नाम काटी दे तो लोकतंत्र में इस से घातक और क्या बात होगी??

चुनाव आयोग का सम्मान होना ही चाहिए किंतु इसके लिए आयोग को भी निष्पक्ष दिखना ही होगा।

–अतिथि सम्पादक,
महावीर सिंह, पूर्व आइ ए एस



पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्तति, सिंजारा, अश्वत्थ मारूती पूजन, व्यतिपात पुण्य है। आज शुक्र मिथुन राशि में प्रातः 8:56 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौचड्डिया: शुभ 7:32 से 9:12 तक, चर 12:33 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:13 से 5:34 तक।

राहुकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:52, सूर्यास्त 7:14

राशिफल

शनिवार 26 जुलाई, 2025

सावन मास, शुक्ल पक्ष, द्वितीया तिथि, शनिवार, विक्रम संवत 2082, आश्लेषा नक्षत्र दिन 3:52 तक, व्यतिपात योग रात्रि 4:06 तक, बालव करण दिन 11:02 तक, चन्द्रमा आज दिन 3:52 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क चन्द्रमा-कर्क, मंगल-सिंह, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृष, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज चन्द्र दर्शन, उत्तर श्रृंगोन्तति, सिंजारा, अश्वत्थ मारूती पूजन, व्यतिपात पुण्य है। आज शुक्र मिथुन राशि में प्रातः 8:56 पर प्रवेश करेगा।
श्रेष्ठ चौचड्डिया: शुभ 7:32 से 9:12 तक, चर 12:33 से 2:14 तक, लाभ-अमृत 2:13 से 5:34 तक।
राहुकाल: 9:00 से 10:30 तक। सूर्योदय 5:52, सूर्यास्त 7:14



अर्पिता माथुर

क्या हम सच में चौंद पर पहुँच गए है या अब भी पुरानी सोच में जकड़े है?।
“सोचिए, जिस लड़की ने तीन साल पहले अपने सपनों की शादी की थी, वही दहेज के बोझ से दबकर अपनी जान दे बैठी।”

राजस्थान के जयपुर में हाल ही में दो विवाहित महिलाओं की मौत की खबर आई। वैशाली नगर में तीन साल पहले लव मैरिज करने वाली महिला ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर श्याम नगर में एक और विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई जहाँ पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। ये घटनाएँ चौकता है और सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम सच में चौंद पर पहुँच गए हैं या अब भी पुरानी सोच में जकड़े

है?। और भी कई ऐसी घटनाओ ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम चाहे चौंद तक पहुँच जाए लेकिन समाज की कुछ रीति-रिवाजों का बोझ जीवन भर सहना पड़ेगा। वैसे रीति-रिवाजों के विरोध में नहीं हूँ मैं लेकिन कुछ रीति-रिवाजों का अपना ऐतिहासिक महत्त्व रहा है, बस समाज ने बिना ज्ञान के अपनी मानसिकता के बल पर अन्य प्रकार से उन्हें ग्रहण किया है और अब आने वाली पीढ़ी पर थोप रहे है।

न केवल भारत में बल्कि यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में भी दहेज प्रथा का लम्बा इतिहास है। भारत में इसके और भी कई नाम है जैसे हूँडा या वर-दक्षिणा। इतिहास में इसे एक परम्परा के रूप में देखा जाता था जिसका ऐतिहासिक सन्दर्भ कई लेखों और चित्रों में भी मिलता है। जिसे यहाँ प्रदर्शित करना एक नयी बहस शुरू कर देगा। क्योंकि मेरा और मेरे जैसे कितने पत्रकारों का यही मकसद रहने वाला है कि इस प्रथा को सही ढंग से प्रस्तुत किया जाये न कि जंग से प्रस्तुत किया जाए... खैर.. भारत में दहेज, भले ही वर्ष 1961 से दहेज निषेध अधिनियम के तहत अवैध घोषित है, फिर भी इसे आज भी एक सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जाता है। वधू यानि लड़की के परिवार द्वारा नक्रद या वस्तुओं के रूप में यह वर यानि लड़के के परिवार को दिया जाता है। कई परिवार इसे विवाह का जरूरी हिस्सा मानते है और अक्सर इसे उपहार का नाम

आँकड़ों की बात की जाए तो साल 2017 से 2022 के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल औसतन 7,000 दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुई। वैसे में ये कहूँगी की के आँकड़ें अपवादित भी हो सकते है क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है उसकी तरफ एक इशारा है। वहीं दहेज के लिए तंग करने पर कानून सख्त सजा देता है जैसे धारा 498 -ए: अगर पति या उसके घरवाले दहेज की मांग करके पत्नी को परेशान करें, तो उन्हें 3 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 406: अगर पत्नी का गहना या उसका सामान वापस नहीं करते, तो 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो

देकर रूप में ढाब दिया जाता है। समाज में अभी भी ये मानसिकता नजर आती है जहाँ उस लड़की की अहमियत उसके जीवन की उपलब्धियों से नहीं, उसकी शिक्षा से नहीं, उसके संस्कारों से नहीं नापी जाती है, बल्कि वह कितना दहेज लेकर आई, इससे तय की जाती है। और इसी दबाव के कारण परिवार दहेज की मांगों को पूरा करने के लिये मजबूर हो जाते है, और यही मजबूरी बन जाती है बेटियों की जिन्दगी का कलंक उरपीड़न, हिंसा और मौत के रूप में। कुछ बेटियां संस्कारों और माता पिता के सम्मान को बचाने के बोझ तले पूरी जिन्दगी गुजार देती है।

कईकों की बात की जाए तो साल 2017 से 2022 के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल औसतन 7,000 दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुई। वैसे में ये कहूँगी की के आँकड़ें अपवादित भी हो सकते है क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता और हम अपने अधिकारों के प्रति कितने जागरूक है उसकी तरफ एक इशारा है। वहीं दहेज के लिए तंग करने पर कानून सख्त सजा देता है जैसे धारा 498 -ए: अगर पति या उसके घरवाले दहेज की मांग करके पत्नी को परेशान करें, तो उन्हें 3 साल तक जेल और जुर्माना हो सकता है। धारा 406: अगर पत्नी का गहना या उसका सामान वापस नहीं करते, तो 3 साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो

सोना प्रत्यक्ष रूप मेंईस युद्ध में शामिल थी। कारगिल- 3000 भारतीय सैनिकों ने भाग लिया वहीं पाकिस्तान के नियमित सैनिकों के अलावा करीब 5000 घुसपैटीयें ने भी पाक सैनकों की मदद की थी। भारतीय सेना ने इस लड़ाई में बोफोर्स तोपों का प्रयोग किया इन तोपों ने दुश्मनों पर कहर बरपा। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के अंतर्गत कठिन भौगोलिक परिस्थतियों के बावजूद थल सैनिकों की सहायता की थी। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के अंतर्गत पाकिस्तानी बंदरगाहों विशेषतया कराची बंदरगाह की नाके बंदी

है वहीं इस लड़ाई में भी पाकिस्तानी शासकों एवं उसकी सेना की इतिहास को दोहराते हुए करारी पराजय हुई थी। पाकिस्तान की सेना और तथाकथित कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की जर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। संघर्ष की प्रारम्भिक अवस्था में पाकिस्तान ने दावा किया कि लड़ने वाले उसके नियमित सैनिक नहीं है वरन वे सभी कश्मीरी उग्रवादी-जिहादी है। पाकिस्तान के इस सफेद झूट का शीशू ही पर्दाफाश हो गया क्योंकि युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों, हथियारों और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी बंदरगाहों विशेषतया कराची बंदरगाह की नाके बंदी कि जिससे पाक सैनिकों को कोई मदद नहीं मिल सके। भारतीय नौसेना की उत्तरी एवं पश्चिमी फ्लीट ने उत्तरी अरब सागर के क्षेत्र में आक्रमक पेट्रोलिंग कर पाकिस्तान के समुद्रीय व्यापार के लिये गम्भीर चुनौती उत्पन्न कर उसके सामुद्रिक व्यापार को क्षति पहुंचाई। इस लड़ाई में भारतीय सेना के तीनों अंग थल,वायु एवं नौ सेना परस्पर अनुकरणीय समन्वय का परिचय दिया जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में भी हमें विजयी प्राप्त हुयी। युद्ध समाप्तिके तुरंत बाद में पाकिस्तान ने दावा किया उसके मात्र 375 सैनिक ही मारे गए हैं लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि पाक के तकरीबन चार हजार सैनिक करगिल संघर्ष में मारे गए हैं। भारतीय

पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्यभर में “बर्तन बैंक” बड़ी पहल बना



विधवा, एससी, एसटी जैसे वर्गों के लिए आधा किराया माफ कर सकती है। राज्य में अजमेर जिले में 27, अलवर में 30, बालोतरा 27, बांसवाड़ा 30, बांग में 24, बाड़मेर में 30, ब्यावर में 18, भरतपुर में 21, भीलवाड़ा में 30, बीकानेर में 27, बुंदी में 15, चित्तौड़गढ़ में 30, चूरू में 21, दौसा में 30, डींग में 15, धौलपुर 20, डोडवाना-कुचामन में 21, दूंगरपुर में 30, श्रीगंगानगर में 27, हनुमानगढ में 21, जयपुर में 30, जैसलमेर में 21, जालौर में 30, झुंझुनूं में 30, झालावाड़ में 24, जोधपुर 30,

सकते है। धारा 304-बी: अगर शादी के 7 साल के अंदर दहेज की वजह से महिला की संदिग्ध मौत हो जाए, तो 7 साल से लेकर उन्कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकी दहेज का विवाह के साथ अटूट संबंध है लेकिन दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का अनुच्छेद 3 निर्दिष्ट करता है कि दहेज देने या लेने का दंड उन उपहारों पर लागू नहीं होता है जो दूल्हा या दूल्हन को शादी के समय दिए जाते है जब उनकी कोई मांग नहीं की जाती है।

गॉव हो या शहर, अमीर हो या गरीब – दहेज प्रथा को जड़ें बहुत गहरी हैं जिसका दूसरा छोर दूढ़ने से भी नहीं मिलेगा। जहाँ एक और महिलाओं को अब भी यानि मॉडर्न समाज में दहेज के लिये उल्टीड़न, मारपीट और आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जाँच प्रक्रियाएँ इतनी लंबी होती हैं की दोषियों को सजा मिलना और बेकम्पूर को न्याय मिलना ऊँट के मुँह में जीरा मिलने समान है। सबसे बड़ी समस्या तो सोच की ही है. बेटों को आज भी ‘परया धन’ समझा जाता है। वहीं दिखावा और समाज में ‘स्टेटस मेन्टेन’ करने की होड़ मची है । अपराधियों में कानून का डर ही नहीं है क्योंकि कई केस दबा दिए जाते हैं या रिपोर्ट नहीं होते। अपराधियों के हॉसल और बुलंद हो जाते है। कुल मिलाकर समस्या समाज की मानसिकता में है। दोनों पक्षों को अपना अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ाना है चाहे आंतरिक स्थिति

–अर्पिता माथुर (पत्रकार)

कारगिल युद्ध : भारतीय सेना और सैनिकों की गौरव गाथा

सेना के मुताबिक 543 अफसर और जवान शहीद हुए जबकि करीब 1३00 जख्मी हुए। महज 3000 भारतीय सैनिक को युद्ध बंदी बनाया गया था। कारगिल संघर्ष के समय जहाँ अमेरिका ने पाकिस्तान को नियन्त्रण रेखा के उल्लघन का दोषी माना था वहीं 8 देशों, यूरोपियन यूनियन एवं के क्षेत्रीय संघटन ने भी पाकिस्तान की आलोचना कर संघर्ष समाप्त करने एवं नियन्त्रण रेखा के उल्लघन को रोक कर संघर्ष के पूर्व वाली स्थिती पर लोटने को कहा। अमेरिकन राष्ट्रपति क्लिंटन और नवाज शरीफ के संयुक्त व्यक्तय में नियन्त्रण रेखा का सम्मान करते हुए भारत-पाकिस्तान के विवादों को बातचीत से शांतीपूर्ण तरीकों से सुलझाने को कहा। चारों ओर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज़ शरीफ ने बचे हुए पाकिस्तान के सैनिकों को भारतीय सीमा के अन्दर वाले क्षेत्र से पीछे हट जाने का आदेश दिया। भारत की विजय के साथ 26 जुलाई 1999 को संघर्ष समाप्त हुआ। कारगिल युद्ध में भारत की विजय की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। समस्त भारत में इस कारगिल युद्ध के दौरान अद्वुत राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना देखने को मिली थी। वहीं पाकिस्तान की पराजय के कारण पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़

गई जिसकी परिणति में नवाज़ शरीफ निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट कर वहां की सेना के प्रमुख परवेज़ मुशर्रफ़ राष्ट्रपति बन गए। कारगिल युद्ध के अनेकों शूरवीर बहादुर एवं फोलादी इरादों वाले जवानों में अतुल्य योगदान, विक्रम बत्रा एवं योगेन्द्र यादव तो प्रमुख हैं ही, भारत को उनके और उनके साथियों की वीरता तथा फोलादी देश भक्ति के इरादों से युद्ध में निर्णायक विजयश्री मिली थी। इस लड़ाई में मुब्छा विजय टाईगर हिल्स पर कब्ज़े पर थी।

कारगिल युद्ध के उपरोक्त नायकों के अतिरिक्त कारगिल संघर्ष के अन्य हीरों यथा कैप्टिन जेरी प्रेमराज, कैप्टिन शशि भूषण घडियाल, सुखेदार मुशनाथ सिंह एवं हवलदार सीसरमन गिल के योगदान को भी समूचा राष्ट्र हमेशा याद रक्खेगा। कारगिल विजय पर्व के 25वीं वर्ष गाँठ के मोके पर समूचा भारत कारगिल संघर्ष के समस्त शहीदों को शत: शत: नमन करता है और उनके देशभक्ति के जज्बे को सलाम भी। समूचा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस के मोके पर भारत की अखंडता पर तिरछी नजर रखने वालों को कड़ी चेतावनी देता है कि वे अपनी नापाक हकतों से बाज आयाँ जय हिंद जय किसान जय जवान। भारत का बच्चा करें उनका सम्मान और सलाम।

–डॉ. जे.के. गर्ग,

पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक कॉलेज शिक्षा जयपुर

शादी व दूसरे सामाजिक समारोह के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम स्थल के आसपास कचरे के ढेर के बजाय साफ-सफाई नए राजस्थान की सुखद तस्वीर है। राज्य सरकार ने क्लीन कुकिंग को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की व्यवस्था की है ताकि सरकारी और निजी कार्यक्रम में डिस्पोजल का उपयोग न करना पड़े। राज्यभर में इसी सोच को साकार करने की दिशा में 1०00 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किये है।

बर्तन बैंक के एक सेट में स्टील की एक प्लेट, तीन कटोरी, एक चम्मच एवं एक गिलास कुल छः बर्तन होते हैं। एक ग्राम पंचायत में इनके 400 सैट उपलब्ध कराए गए हैं। प्रति ग्राम पंचायत 1 लाख रुपये मूल्य के बर्तनों की खरीद की गई है। प्रति सेट 3 रूपए किराया लिया जाता है ताकि इनका रखखाव करने वाले राजीविका के महिला स्वयं सहायता समूह को योजना संचालन में आसानी हो। ग्राम पंचायत



बुंदी में 15, चित्तौड़गढ़ में 30, चूरू में 21, दौसा में 30, डींग में 15, धौलपुर 20, डोडवाना-कुचामन में 21, दूंगरपुर में 30, श्रीगंगानगर में 27, हनुमानगढ में 21, जयपुर में 30, जैसलमेर में 21, जालौर में 30, झुंझुनूं में 30, झालावाड़ में 24, जोधपुर 30, विधवा, एससी, एसटी जैसे वर्गों के लिए आधा किराया माफ कर सकती है। राज्य में अजमेर जिले में 27, अलवर में 30, बालोतरा 27, बांसवाड़ा 30, बांग में 24, बाड़मेर में 30, ब्यावर में 18, भरतपुर में 21, भीलवाड़ा में 30, बीकानेर में 27, बुंदी में 15, चित्तौड़गढ़ में 30, चूरू में 21, दौसा में 30, डींग में 15, धौलपुर 20, डोडवाना-कुचामन में 21, दूंगरपुर में 30, श्रीगंगानगर में 27, हनुमानगढ में 21, जयपुर में 30, जैसलमेर में 21, जालौर में 30, झुंझुनूं में 30, झालावाड़ में 24, जोधपुर 30,

विधवा, एससी, एसटी जैसे वर्गों के लिए आधा किराया माफ कर सकती है। राज्य में अजमेर जिले में 27, अलवर में 30, बालोतरा 27, बांसवाड़ा 30, बांग में 24, बाड़मेर में 30, ब्यावर में 18, भरतपुर में 21, भीलवाड़ा में 30, बीकानेर में 27, बुंदी में 15, चित्तौड़गढ़ में 30, चूरू में 21, दौसा में 30, डींग में 15, धौलपुर 20, डोडवाना-कुचामन में 21, दूंगरपुर में 30, श्रीगंगानगर में 27, हनुमानगढ में 21, जयपुर में 30, जैसलमेर में 21, जालौर में 30, झुंझुनूं में 30, झालावाड़ में 24, जोधपुर 30,

बुंदी में 15, चित्तौड़गढ़ में 30, चूरू में 21, दौसा में 30, डींग में 15, धौलपुर 20, डोडवाना-कुचामन में 21, दूंगरपुर में 30, श्रीगंगानगर में 27, हनुमानगढ में 21, जयपुर में 30, जैसलमेर में 21, जालौर में 30, झुंझुनूं में 30, झालावाड़ में 24, जोधपुर 30,

करोली 24, खैरथल-तिजारा 15, कोटा 20, कोटपुतली- बहरोड़ 20, नागीर 24, पाली 24, फलोदी 24, प्रतापगढ़ 24, राजसमंद 24, सलुम्बर में 20, सर्वाइवाधोपुर में 21, सीकर में 30, सिरोही में 20, टोंक 21 और उदयपुर में 30 ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

इस योजना के सफल संचालन से भरतपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता के प्रति नई चेतना आई है। गरीब परिवारों को भी टैट किराये से राहत मिली है। शादी समारोह में टैट किराये में लगने वाला हजारों रूपये का खर्च बचने से बड़ी राहत मिली है, कचरे के ढेर, दुर्गंध, पर्यावरण क्षण का कुछ हद तक समाधान हुआ है। जिले की पंचायत समिति सेवर में ग्राम पंचायत हथैनी, जधीना और जाटौली रथवान, पंचायत समिति भुसावर की बल्लभगढ, निठार और पथैना, उच्चैन की भैंसा, पिचुना और सहना, वैर की समराया, सरसैना और पाली, रूपवास की

औडेलगढी, निभेरा और चैकोरा, नदबई की लखनपुर, कटारा और परसवारा एवं बयाना की बंधबैरठा, सालाबाद और गाजीपुर ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक खोले गए हैं। राज्य में इसके अतिरिक्त एक लाख लाभार्थियों को नि:शुल्क इंडव्रेशन कुकटॉप वितरित करने का निर्णय लिया गया है। वेस्ट 2 वैल्थ पार्क्स और क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डवलपमेंट सेंटर जैसे नवाचारों से पर्यावरण संरक्षण को तकनीकी मजबूती दी जा रही है। इसे गावों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे ग्रामीणों को भी सामूहिक आयेजनों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की प्रेरणा मिलेगी।

यह लेख हरिओम सिंह गुर्जर, संयुक्त निदेशक, भरतपुर सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय और संतोष कुमारवत, सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), पंचायतीराज विभाग ने लिखा है।

कन्या	कथ्या
	
आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।	आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

शासन सचिव ने प्री वेटरिनरी टेस्ट को पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए

शासन सचिव पशु पालन डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित

जयपुर। शासन सचिव पशुपालन, गोपालन और मत्स्य डॉ समित शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को शासन सचिवालय में राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, (राजुवास) बीकानेर/जोबनेर, जयपुर के संघटक पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालयों एवं संबद्ध वेटेरिनरी कॉलेजों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से अगस्त में आयोजित होने वाले राजस्थान प्री वेटेरिनरी टेस्ट पर चर्चा हुई। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि यह परीक्षा पूर्ण रूप से निष्पक्ष, कड़ाचार रहित और पारदर्शी तरीके से करवाना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की अनियमितता बिल्कुल बरदाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी करने के सख्त निर्देश दिए।

■ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पारदर्शी और मेरिट के आधार पर हो

उन्होंने कहा कि परीक्षा और प्रवेश की पूरी प्रक्रिया केंद्रीकृत होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है अगर ऐसा मामला कहीं भी सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों को गंभीर परिणाम मुगतने होंगे।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान प्री वेटेरिनरी टेस्ट की परीक्षा 3 अगस्त को प्रदेश के चार शहरों उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के 3३ परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। शासन सचिव ने निर्देश दिए कि इन केंद्रों पर शुचितापूर्ण परीक्षा की सारी माकूल व्यवस्थाएं आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने राजुवास को निर्देश दिए कि परीक्षा से पहले मानक संचालन प्रक्रिया जारी

करने आदि नियमों का पालन करना होगा अन्यथा कॉलेजों की असंबद्धता के लिए राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद को अनुशंसा भेज दी जाएगी। उन्होंने सभी कॉलेजों को सभी प्रकार के उपकरण और औजार की उपलब्धता और उनका उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि कॉलेज के संचालन में भी पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिए कि पूरे सत्र का कैलेंडर पूर्व में ही तैयार करें और उसकी अनुपालना भी सुनिश्चित करें साथ ही सत्र समयपर प्रारंभ हों और समय पर समाप्त हों ऐसी व्यवस्था भी सुनिश्चित हो।

बैठक में शासन उपसचिव संतोष करोल, राजुवास के प्रो वाइस चांसलर डॉ हेमंत दाधीच, डॉ ब्रजनंदन श्रृंगी, निदेशक शोध, डॉ प्रकाश, डॉ अशोक डांगी, डॉ साकार पालेचा सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

देवनानी का शहीदों को नमन किया

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कारगिल विजय दिवस पर शहीदों के श्रद्धापूर्वक नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिन उन वीर सपूतों की याद में समर्पित है जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में अदम्य साहस दिखाया और भारत की सहर्दों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

हेरिटेज निगम 26 जुलाई को मनाएगा सिंजारा तीज महोत्सव

जयपुर। नगर निगम हेरिटेज जयपुर की ओर से 26 जुलाई शनिवार को सिंजारा तीज महोत्सव आयोजन किया जाएगा। हेरिटेज निगम महापौर कुसुम यादव के नेतृत्व में आदर्श नगर में होने वाले इस आयोजन में शहरवासियों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए जाएंगे। सिंजारा तीज महोत्सव में राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता को दर्शाया जाएगा। जिसमें कई प्रतियोगिता आयोजित की गई हैं। मेंहदी प्रतियोगिता, साफा बंधाई प्रतियोगिता, लहरिया प्रतियोगिता, बनी ठनी प्रतियोगिता का आयोजन शहरवासियों के लिए किया जाएगा।

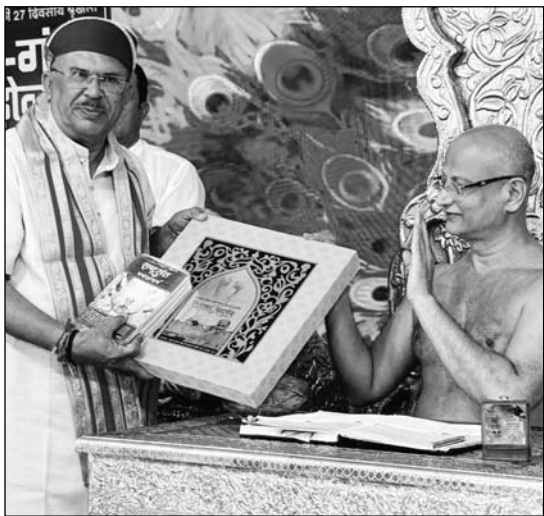
बैंक से रुपये लेकर निकले युवक से नौ लाख रुपए लूटे

जयपुर। बजाज नगर थाना इलाके में बैंक से रुपये लेकर निकले युवक से नौ लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मों बताकर बदमाश कार में डालकर युवक का अपहरण कर ले गए थे और दो किलोमीटर दूर रास्ते में फेंककर बदमाश फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनाक्रम की जानकारी लेकर मामले की जांच कर रही है।

सहायक पुलिस आयुक्त (एसोपी मालवीय नगर) आदित्य पूनिया ने बताया कि बजाज नगर थाना इलाके में स्थित दुर्गापुरा एस्पल कट के पास आरबीएल बैंक से नौ लाख रुपये लेकर निकले पीडित जयवंत का बैंक के बाहर आए चार युवकों ने खुद को पुलिसकर्मों बताकर उसका अपहरण कर ले गए। जिसके बारे में वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना

■ पुलिसकर्मों बताकर बदमाश कार में डालकर युवक का अपहरण कर ले गए थे और दो किलोमीटर दूर रास्ते में फेंककर बदमाश फरार हो गए

दी। अपहरणकर्ताओं ने दो किलोमीटर दूर ले जाकर जीटी के पास रास्ते में फेंक कर फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने अपहरण जयवंत की जानकारी कर तलाश शुरू की। जीटी के पास मिलने पर पुलिस उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई। पीडित की ओर से अपहरण कर लूट मामले में शिकायत नहीं दी गई।



विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को उदयपुर में आचार्य पुलक सागर की 27 दिवसीय प्रवचन श्रृंखला में पहुंचकर उनसे आशीर्वाद लिया, देवनानी ने कहा कि आचार्य पुलक सागर के प्रेरणादायी विचारों से आध्यात्म, संयम, सदाचार एवं आत्मशुद्धि की भावना जागृत होती है। उन्होंने कहा कि ओजस्वी प्रवचनों ने जनमानस में आध्यात्मिक चेतना और नैतिक मूल्यों के प्रति नई ऊर्जा का संचार भी होता है।

न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश जारी

जयपुर। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर प्रदेश न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश शुक्रवार को भी जारी रहा। हाईकोर्ट के आदेश की पालना में डीजे कोर्ट प्रशासन ने कर्मचारियों को काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की है।कर्मचारी संघ के संरक्षक बद्रीलाल चौधरी ने बताया कि हमारे आंदोलन को कई वकील संगठनों का समर्थन मिला है। जब तक

झालावाड़ हादसे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने जताया दुःख

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने झालावाड़ जिले के मनोहरथाना ब्लॉक में एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिरने से हुई जनहानि को दुःखद और अत्यंत व्यथित करने वाली बताया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने इस संदर्भ में स्थानीय प्रशासन से राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली है। त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए कहा है।

पुलिस ने 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया

■ डीजे कोर्ट प्रशासन ने कर्मचारियों को काम पर नहीं लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की

कैडर पुनर्गठन को लेकर चल रही हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम सामूहिक अवकाश जारी रखेंगे। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने दो साल पहले कैडर पुनर्गठन को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन राज्य सरकार अभी तक उस पर निर्णय नहीं कर पाई है।

जबकि दूसरी ओर राज्य कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन पूर्व में ही किया जा चुका है। इसके अभाव में न्यायिक कर्मचारियों को हर माह हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान होने के साथ-साथ पदोन्नति भी समय पर नहीं हो पा रही है।

आबकारी निरोधक टीम ने 6० कार्टून अवैध शराब बरामद कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया

जयपुर। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध मदिरा निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर अंकुश लगाने के लिए जारी विशेष निरोधकत्मक अभियान के तहत आबकारी निरोधक टीम जयपुर शहर व ग्रामीण की संयुक्त कार्यवाही में नकली होलोग्राम की 6० कार्टन अवैध शराब जब्त की गई एवं पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त आबकारी आयुक्त ज्ञान जयपुर ने बताया कि जयपुर में नकली होलोग्राम की अवैध शराब जब्त की गई। आबकारी निरोधक दल द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र से स्कॉर्पियो वाहन से 30 कार्टन नकली होलोग्राम की देशी शराब बरामद की गई। इसी क्रम में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक स्कूटी से 6 कार्टन



नकली होलोग्राम की 6० कार्टन अवैध शराब सहित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया ।

देशी शराब 288 पन्वे बरामद किए। झोटवाड़ा क्षेत्र में 305 पन्वे आरएमएल शराब एवं दादी का फाटक जयपुर क्षेत्र

जर्जर भवनों एवं संरचनाओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने सख्त निर्देश दिये

जयपुर। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने जिले में स्थित जर्जर एवं खतरनाक भवनों तथा संरचनाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में ऐसे भवन आमजन की जान-माल के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं, अतः इन्हें प्राथमिकता से चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्त किया जाए। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने कहा कि नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम तथा ग्राम पंचायत स्तर पर अभियान चलाकर आमजन के आवास, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय भवन सहित ऐसे सभी भवनों की सूची तैयार की जाए, जो उपयोग में

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने झालावाड के पीपलोदी स्कूल हादसे पर संवेदना व्यक्त की

जयपुर। झालावाड़ जिले के पीपलोदी क्षेत्र में हुए विद्यालय भवन हादसे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि यह एक अत्यंत पीड़ादायक घटना है और पूरा भाजपा परिवार शोकसंतप्त परिवजनों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार इस कठिन समय में हर संभव संबल और सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दुखी परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। राहत और पुनर्वास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इस हादसे की तत्काल जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें सीईओ, जिला परिषद झालावाड़, एसडीएम मनोहरथाना और अधीक्षण अभियंता झालावाड़ को शामिल किया गया है। जांच समिति शीघ्र ही दुर्घटना के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही सभी स्थितों और विद्यालयों को भवनों की रियल्टी को लेकर अलर्ट जारी किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए सभी जर्जर भवनों को चिह्नित कर सुरक्षित रूप से ध्वस्त करने की

कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, इसके लिए भी स्थानीय निकायों को पत्र जारी किए गए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि इस दुःखद समय में राजनीति करना निंदनीय है। हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य करना चाहिए। जो लोग आज बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वे स्वयं कभी शिक्षा मंत्री रहे हैं। डोटासरा को ध्यान रखना चाहिए कि यह भवन काफी पुराना बना हुआ है, लेकिन यह समय राजनीति का नहीं है।

उन्होंने यह भी बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों में सक्रिय सहयोग किया। चिकित्सा व्यवस्था पर राठौड़ ने बताया कि सरकार ने विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भेज दी है और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए पाबंद किया गया है। उन्होंने बताया कि हमने पहले भी समय-समय पर अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। कुछ अधिकारियों की लापरवाही सामने आने पर निर्लेनकों की कार्रवाई भी की गई है। यह घटना अत्यंत दुःखद है और हमने अपने मासूम बच्चों को खो दिया है, जिसका दुःख हम सबके मन में है।

सार-समाचार केनरा बैंक डॉक्टर्स म्यूजिक प्रीमियम लीग सीजन 4 का शुभारम्भ

जयपुर। केनरा बैंक डीएमपीएल सीजन 4 के संयोजक डॉ संदीप निशानवन ने बताया कि 25 जुलाई को इसके चौथे संस्करण का शुभारंभ आरआईसी जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सीईओ व मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने किया ,कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि गीतांजली मेडिकल कॉलेज जयपुर के प्रिंसिपल व डीन डॉ अशोक गुप्ता व बॉलीवुड सिंगर रवींद्र उपाध्याय थे। लीग के आयोजन अध्यक्ष डॉ संजीव गुप्ता ने बताया कि उदघाटन सत्र के मुख्य अतिथि पवन अरोड़ा ने इस तरह कि प्रतियोगिता की आवश्यकता बताते हुए इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि व डीएमपीएल के ब्रांड एंबेसडर रवींद्र उपाध्याय ने कहा कि डॉक्टर्स में भरपूर टैलेंट है और वे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं।चीफ कॉर्डिनेटर डॉ हर्षुल टाक ने बताया कि गौरी ज्वेलर्स से गौरी माहेश्वरी व महिमा ग्रुप से धीरेंद्र मदान ने भी इस अनूठे आयोजन की तारीफ़ करते हुए इस आयोजन से जुड़े। मंच संचालन डॉ रवींद्र सिसोदिया ने किया।

महिलाओं ने तीज उत्सव मनाया



जयपुर। रंगोली गार्डन की महिलाओं ने यहां वैशाली नगर स्थित एक होटल में तीज उत्सव पारंपरिक ढंग से मनाया। कार्यक्रम में करीब एक सौ से अधिक आकर्षक लिबास में सजीली महिलाओं ने उत्साह से हिस्सा लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मिसेज राजस्थान-2०25 निधि शर्मा व रजनी मेहता ने विनर्स को तीज क्वीन, लहरिया क्वीन, रैपवांक क्वीन जैसे टाइटल्स से भी नवाजा। आयोजक डोली छाबड़ा व महिमा शर्मा ने बताया कि आकर्षक लिबास में सभी महिलाओं तीज पर्व के पारंपरिक लोकगीतों पर कदम थिरकाए। साथ ही आकर्षक रैपवांक के दौरान तीज पर्व के इन्द्रनुषी रंग बिखरे। कार्यक्रम के दौरान कई रोचक गेम्स ने भी माहौल को खुशनुमा बनाया। कार्यक्रम में डाइटिशियन कीर्ति जैन, नीतू, रीना और नीलम आदि मौजूद रहीं। संचालन एंकर करने ने किया।

मार्केट में उतरे दो नए इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स



जयपुर। पियाजियो व्हीकल्स ने अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर सेगमेंट में दो नए मॉडल्स- आपे ई-सिटी अल्ट्रा और आपे ई-सिटी एफएक्स मैक्स लॉन्च किए हैं। ये दो नए गाड़ियों खासतौर पर भारत की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। पियाजियो व्हीकल्स प्रा. लि. के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डिएगो ग्राफी ने कहा, ”भारत में ईवी की माँग तेज़ी से बढ़ रही है और हम चाहते हैं कि हमारे वाहन न सिर्फ टिकाऊ हों, बल्कि लोगों की आजीविका भी बेहतर करें।” पियाजियो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट- सीबी डॉमेस्टिक बिजनेस और रिटेल फाइनेंस, अमित सागर ने कहा, ”ग्राहकों की जरूरत है- लंबी रेंज, दमदार बैटरी और कम खर्च। यही सोचकर हमने ये नए मॉडल्स बनाए हैं, जो हर मायने में भरोसेमंद हैं।” आपे ई-सिटी अल्ट्रा देता है 2३6 किमी की रेंज, 9.५5 किलोवाॉट की पावर, बूस्ट मोड, क्लाईब असिस्ट और स्मार्ट 4जी टेलीमैटिक्स जैसे एडवांस्ड फीचर्स।

पुस्तक “निज से, निज को” का लोकार्पण समारोह 27 को

जयपुर। प्रवीणचंद्र छाबड़ा द्वारा रचित पुस्तक "निज से, निज को" का लोकार्पण समारोह आगामी 27 जुलाई 2०2५ (रविवार) को प्रातः 1०:३० बजे जयपुर स्थित पिक सिटी प्रेस क्लब, नारायण सिंह सर्कल में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में विनोद शंकर रवे (यूत्यूव् न्यायधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय) और नंद भारद्वाज (हिंदी और राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ कवि, कथाकार एवं समीक्षक) विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।समारोह के विशिष्ट वक्ता होंगे, विजय त्रिवेदी, जो पूर्व एडिटर एनडीटीवी इंडिया, लेखक एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सिम विक्रेताओ को गिरफ्तार किया



जयपुर। शास्त्री नगर थाना पुलिस ने संदिग्ध सिम विक्रेताओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन सिम विक्रेताओ को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपितों से पूछताछकी जा रही है। पुलिस उपायुक्त जयपुर उतार करण शर्मा ने बताया कि शास्त्री नगर थाना पुलिस ने संदिग्ध लोगों को सिम कार्ड बेचान करने वाले पीएसओ के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बिकार मोबाईल पॉइंट के संचालक मोहम्मद बिकार निवासी शास्त्री नगर ,बरकत मोबाईल पॉइन्ट के संचालक फारुख निवासी नाहरी का नाका जयपुर और कुरेशी मोबाईल पॉइन्ट से आसिफ हुसैन निवासी शास्त्री नगर को गिरफ्तार किया है और साथ ही बेची गयी संदिग्ध सिम कार्ड के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

देवनानी से नव नियुक्त कुलगुरु अग्रवाल की मुलाकात

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से यहां विधान सभा में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के नव नियुक्त कुलगुरु सुरेश कुमार अग्रवाल ने शिष्टाचार भेंट की। अग्रवाल ने देवनानी से विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले नवाचारों पर चर्चा की।

नेशनल पावरलिफ्टिंग में जीते मैडल

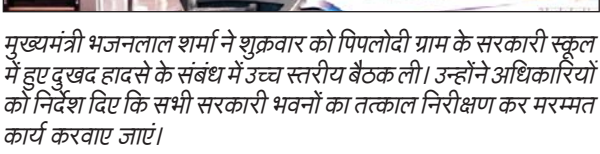
जयपुर। नेशनल पावरलिफ्टिंग 2०25 में राजस्थान के चार खिलाड़ियों हर्ष, सोनू, आयुष, शुभम ने जीते मेडल। चारों खिलाड़ी जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा के रहने वाले हैं ! कोच नैतिक जांगिड़ (राष्ट्रीय पदक विजेता) शिव शक्ति जिम ने बताया की चारों खिलाड़ियों का दो महीने बाद होने वाले इंटरनेशनल गेम में भी चारों हाइयां हैं। विद्याधर नगर विधानसभा के जन सेवक विष्णु प्रताप सिंह द्वारा इन सभी खिलाड़ियों का तलवार भेंट कर सम्मान किया गया।

‘सभी जर्जर सरकारी भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत करायें’

मुख्यमंत्री भजनलाल ने पिपलोदी हादसे के बाद बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के भवनों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये

जयपुर, 25 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर झालावाड़ जिले के पिपलोदी ग्राम के सरकारी स्कूल में हुए दुखद हादसे के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली। उन्होंने समस्त जिलों के जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्यकारी एंजेंसी, समसा एवं आरएसआरडीसी सहित, संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों, विशेष रूप से स्कूलों, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक भवनों का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कार्य करवाए जाएं। इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो 5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

शर्मा ने आगे कहा कि प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीपलोदी हादसे से हम सब दुखी हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ठोस और त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए भवनों के निरीक्षण, मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी विद्यालय की छत गिरने से हुआ हादसा दुखद एवं हृदय विदारक है। इस दर्दनाक हादसे में मासूम बच्चों की मृत्यु से मन व्यथित है। राज्य सरकार दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि असुरक्षित पाये जाने वाले भवनों को तुरंत खाली करवा कर प्रभावितों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास किया जाना चाहिये। गत दो बजट में राज्य सरकार ने विद्यालयों के भवन निर्माण व मरम्मत कार्यों के लिए 625 करोड़ रूपयों का आवंटन किया है।**

प्रावधान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। बैठक के दौरान, पीपलोदी हादसे पर दो मिनट का मौन रखकर मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित, विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे तथा वीसी के माध्यम से संभागीय आयुक्तगण, जिला कलक्टरसं एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी जुड़े।

इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ लगातार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाले दूसरे प्र.मंत्री बने मोदी

मोदी पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं जो सबसे लम्बे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं

नई दिल्ली, 25 जुलाई। नरेंद्र मोदी 25 जुलाई यानी आज लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अभी तक लगातार सबसे लंबे समय तक (16 वर्ष 286 दिन) प्रधानमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड जवाहर लाल नेहरू के पास है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को अपने कार्यकाल के 4078 दिन पूरे कर लेंगे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977 तक लगातार 4077 दिन प्रधानमंत्री रही थीं। अगर राज्य और केंद्र में सरकार का नेतृत्व करने की बात करें तो नरेंद्र मोदी का सभी प्रधानमंत्रियों के बीच एक अलग रिकॉर्ड है। वह गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 24 वर्षों तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं।

- अगर सरकार का नेतृत्व करने की बात की जाए तो मोदी के नाम एक विशेष रिकॉर्ड है। वे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 24 साल तक सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं।
- इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक लगातार 4077 दिन तक प्रधानमंत्री रही थी और मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर चुके हैं।

नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश की स्वतंत्रता के बाद हुआ। वह सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले और प्रधानमंत्री पद पर दो कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। उनके नाम लगातार दो बार निर्वाचित होने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी प्रधानंत्री होने का रिकॉर्ड भी है।

पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने वाले पहले और एकमात्र गैर-कांग्रेसी नेता भी हैं। वह इंदिरा गांधी (1971) के बाद पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले वे पहले प्रधानमंत्री हैं। पंडित नेहरू के अलावा वह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार तीन आम चुनाव जीते हैं।

“उदयपुर फाइल्स” को ... धनखड़ को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जाकर बहस करें। हमने पहले ही 12 दिन खो दिए हैं। प्राधिकरण ने भी आदेश पारित कर दिया है।”

इस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “12 दिन कोई नुकसान नहीं, जितनी पब्लिसिटी, उतना फिल्म को फायदा।”

हालाँकि भाटिया ने मदनी का हवाला देते हुए कहा, ऐसे लोग हमेशा ‘सुपर सेंसर’ की तरह काम करते हैं और फिल्म रिलीज पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं।

“1200 स्क्रीन बुक थीं, पैसा निवेश हो चुका है। हम किस बात को बढ़ावा दे रहे हैं? कि किसी की भावनाएं आहत हों और सिधे कोर्ट से स्टे ले जाएं?”

अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया, बल्कि हाईकोर्ट को विवेकानुसार निर्णय लेने की छूट दी। कोर्ट ने आदेश में कहा: “यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दी है। हाईकोर्ट स्वतंत्र है, जो भी आदेश उचित समझे, पारित कर सकता है।”

धमकी भी दी।

जानकारी के अनुसार, मामले में एक्शन लेते हुए राखस्राम सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय के स्टाफ को निर्लंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, मोना गर्ग, जावेद अहमद, रामविलास लववंशी, कन्हैयालाल सुमन और बद्रीलाल लोधा को तुरंत प्रभाव से निर्लंबित कर दिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने स्कूल के स्टाफ पर कार्यवाही करके इतिश्री कर ली है, जबकि बड़े अधिकारियों पर भी कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा विधायक गोविंद रानीपुरिया, जिला प्रशासन के आला अधिकारी एवं सभी स्थानीय अधिकारियों को बार-बार स्कूल की हालत से अवगत करवाया गया था, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सब आश्वासन ही देते रहे और यह

धनखड़ को उनके इस्तीफे के कुछ दिनों के बाद यह निमंत्रण दिया है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है।(विपक्षी दलों की ओर से राज्यसभा के वर्किंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया गया। विपक्ष ने कहा कि 74 वर्षीय धनखड़ को राज्यसभा में अपना विदाई भाषण तक देने का मौका नहीं मिला। इसी मुद्दे को और जोर देने के लिए विपक्षी दलों ने एक विशेष फेयरवेल डिनर का आयोजन किया है।

विपक्षी सांसद बैनर लेकर चल रहे थे जिसमें ‘एसआईआर- लोकतंत्र पर वार’ लिखा हुआ था। उन्होंने ‘एसआईआर वापस लो’ और ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाये।

एसआई ... (प्रथम पृष्ठ का शेष)

ट्रेनी एसआई सहित, अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि पिपर लीक को लेकर व्यापक स्तर पर जांच चल रही है और अभी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती।

सरकार ने 25 ओटीटी चैनल बैन किए

नई दिल्ली, 25 जुलाई। भारत सरकार ने डिजिटल कंटेंट में बंद रही अश्लीलता को लेकर अब एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने कथित तौर पर अश्लीलसामग्री दिखाने के लिए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म और उनके संबंधित मोबाइल एप्लिकेशन पर बैन लगा दिया है। इनमें उल्लू, एल्ट, देसीफिलक्स और बिग शॉट्स जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अलग-अलग जांच एजेंसियों से पूरी जानकारी हासिल करने के बाद यह फैसला लिया है।

■ **इनमें ऑल्ट, उल्लू, बिग शॉट्स, ड्रीम फिल्म्स आदि बड़े नाम शामिल हैं। आरोप है कि इन पर अश्लील सामग्री प्रसारित की जा रही थी।**

मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इस कदम का उद्देश्य अश्लील और भारतीय कानूनी एवं सांस्कृतिक मानकों का उल्लंघन करने वाले कंटेंट के दिखाए जाने पर रोक लगाना है।

प्रतिबंधित एप्लिकेशन की लिस्ट में प्राइम प्ले, हंटर्स, ड्रीम फिल्म्स, रंगीन और नियोनएक्स वीआईपी भी शामिल हैं। इन प्लेटफॉर्म की अक्सर अपने अश्लील कंटेंट और एडल्ट सीरीज को लेकर आलोचना की जाती रही है, जिसके चलते ये प्लेटफॉर्म अक्सर निशाने पर भी रहते हैं।

सिंहस्थ कुम्भ के लिए नासिक के समीपवर्ती 5 रेल्वे स्टेशन विकसित होंगे

सिंहस्थ कुम्भ में तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। महाराष्ट्र के नासिक-त्र्यंबकेश्वर में 2027 में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के मद्देनजर, रेलवे 1.011 करोड़ रुपये की लागत से आसपास के पांच रेलवे स्टेशनों को विकसित करेगा।

जिन स्टेशनों को विकसित किया जाना है, उनमें नासिक रोड, देवलाली, ओग 1, खेरवाड़ी और कसबे सुकेणे शामिल हैं।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिंदू ने शुक्रवार को सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक, प्रमुख मंडल के मंडल रेल अधिकारी (डीआरएम) और अन्य अधिकारियों ने मंत्रियों तथा रेलवे बोर्ड को इसकी योजना और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी दी।

वैष्णव ने अधिकारियों से महाकुंभ 2025 के अनुभव से प्राप्त सर्वोत्तम

- **रेल्वे एक राउण्डट्रिप सर्किट ट्रेन भी चलाएगा, जो तीन ज्योतिर्लिंगों, त्रयम्बकेश्वर, ओंकारेश्वर व घुण्णेश्वर को आपस में जोड़ेगी।**

कार्यप्रणालियों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को नासिक के सभी निकटवर्ती स्टेशनों पर पूर्णतः सुविधाएँ विकसित करने की सलाह दी। इसके अलावा, सभी पाँचों स्टेशनों पर विभिन्न यात्री सुविधाओं के विकास को योजना है। इनमें कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म, पानी की टंकियां, नये शौचालय और वाटरप्रूफ होल्डिंग एरिया शामिल हैं। सर्कुलरिंग एरिया, रास्ते, प्रवेश/निकास मार्ग और यात्री सूचना प्रणालियों को भी उन्नत करने की योजना है। सिंहस्थ कुंभ में तीन करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए रेलवे बहुत अधिक संख्या में विशेष रेलगाड़ियाँ चलाने की योजना बना रहा है। एक राउंड-ट्रिप विशेष सर्किट ट्रेन भी चलायी जाएगी। यह तीन ज्योतिर्लिंगों- त्र्यंबकेश्वर, घुण्णेश्वर और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी। तीर्थयात्रियों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रमुख स्टेशन पर बड़े होल्डिंग एरिया विकसित किये जा रहे हैं। एक केन्द्रीयकृत कमान और नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह प्रभावी निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और पूर्वानुमानित समय-निर्धारण के लिए एआई उपकरणों से सुसज्जित होगा। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे, तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है।

- **लुटेरे स्विगी व ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉय बनकर दुकान में घुसे थे**
- **बदमाशों ने 20 किलो चांदी, 125 ग्राम सोने के आभूषण तथा 20 हजार रुपए लूटे हैं। मात्र 6 मिनट में लूटपाट कर वे बाइकों से फरार हो गए।**

125 ग्राम सोने के गहने और 20 हजार रुपये नकद दो बैगों में भर लिए। लूट के बाद बदमाश पिस्टल के दम पर शुभम और कर्मचारी को दुकान के बाहर ले गए और बाइक से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद शुभम ने तुरंत अपने पिता

और पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची और शुभम से पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक, लूट की जानकारी शाम करीब 4 बजे मिली। शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात सिर्फ 6 मिनट में अंजाम

सावरकर पर बयान के मामले में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने वीर सावरकर पर विवादस्पद बयान देने के मामले में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दी गई राहत जारी रखते हुए निचली अदालत के समन पर शुक्रवार को अंतरिम रोक की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ा दी दी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एंजी मसीह को पीठ ने कांग्रेस नेता गांधी की विशेष अनुमति याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए कहा कि वह इससे मामले में चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई करेगी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने निचली अदालत के समन पर रोक लगाने से इनकार करने वाले इलाहाबाद उच्च

- **सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के समन पर अंतरिम रोक की अवधि अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है।**

यह भी कहा गया है कि मजिस्ट्रेट का संज्ञान आदेश स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। यह शीर्ष न्यायालय द्वारा स्थापित कानून के विपरीत है। याचिका में दलील दी गई है कि उनकी (राहुल गांधी) टिप्पणियाँ एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थीं। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से शत्रुता या घृणा फैलाना नहीं था। याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके खिलाफ आदालती कार्यवाही वास्तव में उनकी स्वतंत्रता को बाधित करने का एक प्रयास है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश सरकार ने गांधी पर लगाए गए आरोपों के संबंध जारी अदालती समन का समर्थन किया है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक हलफनामा के जरिए अपना जवाब दाखिल किया है।

गांधी ने अधिवक्ता प्रसन्ना एस के माध्यम से दायर अपनी याचिका में दलील दी है कि शिकायत और निचली अदालत (मजिस्ट्रेट) का आदेश धारा 153 ए और 505 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी अपराध को लेकर व्यापक स्तर पर जांच चल रही है और अभी भर्ती रद्द नहीं की जा सकती।

करौली में मारुति वैन-पिकअप भिड़ंत में चार महिलाओं की मौत

दुर्घटना में चार मृतक व 14 घायल जाटव परिवार के तथा एक ही कुटुंब के थे

- **हिण्डीन के बेड़ा वनकी गाँव व मुडियांकापुरा के 17 लोग, महिला, पुरुष व बच्चे, एक वैन में करौली के पास माची गाँव में तीये की बैठक में शामिल होने गये थे। लौटते समय गुडला गाँव के पास पिकअप से सीधी भिड़ंत हो गई।**

पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां से लोगों की मदद एवं निजी वाहनों से घायलों को करौली सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जिनमें से चार महिलाएं गुड्डी पत्नी बिनोद 35, कमला पत्नी रेवती 40, शकुंतला पत्नी कजोड़ी जाटव 60 व मछला पत्नी जगदीश 40 को इयूटी डॉ. ने मृत घोषित कर दिया। इनके अलावा, वाहन चालक दत्त सिंह 50 गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया । बाद में शवों का

पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिये। घटना की गंभीरता को देखते हुए, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गुमनाराम, पुलिस उपाधीक्षक अनुज शुभम, सदर थाना अधिकारी रामदीन शर्मा पुलिस बल के साथ सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। मृतक और घायल एक जाति विशेष जाटव परिवार के और एक ही कुटुंब के थे। इधर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने भी अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामकेश मीणा को घायलों को अच्छा उपचार देने के निर्देश दिए।

सोमवार से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रणनीति बदल दी है, वह अभी तक बिहार के मजदूत सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अब, प्रधानमंत्री मोदी के शनिवार को विदेश यात्रा से लौटने के बाद, ऑपरेशन सिंदूर पर ध्यान देने की योजना बना रहा है। इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन संसद के भीतर और परिसर में, दोनों जगह जारी हैं।

कोचिंग सेंटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिए 15 निर्देश

नयी दिल्ली, 25 जुलाई। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को दो महीने के भीतर निजी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण कराने सहित, 15 बाध्यकारी निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नీट) के अर्धवर्षी 17 वर्षीय एक छात्र की मृत्यु के मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।

विशाखापत्तनम में छात्र की अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। यह दुखद घटना जुलाई में विशाखापत्तनम स्थित आकाश-बायजू संस्थान में हुई थी।

पीठ ने मृतक के पिता सुकदेब साहा की याचिका पर फैसला सुनाते हुए, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ये दिशानिर्देश जारी किए। अदालत ने इसके अलावा केन्द्र सरकार को 90 दिनों के भीतर एक हलफनामा दाखिल कर अनुपालन के संबंध में जानकारी देने का भी निर्देश दिया।

दी गई। जांच के लिए दो टीमें बनाई हैं। सीसीटीवी फुटेज खींचे जा रहे हैं और बदमाशों की बाइक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

जांच में यह भी सामने आया है कि बाइक पर जो नंबर लेट लगी थी, वह फर्जी थी। साथ ही बदमाश दिल्ली की ओर से आए थे। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिख रहा है कि बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर दुकान में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की। घटना का पूरा 6 मिनट का वीडियो सामने आया है, जिसे पुलिस सुराग जुटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है।

मानव रहित यान से मिसाइल का सफल ट्रायल

हैदराबाद, 25 जुलाई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में राष्ट्रीय ऑपन एरिया रेंज (एनओआर) से उन्नत मानवरहित हवाई वाहन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल (यूएलपीजीएम)-वी3 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यूएलपीजीएम-वी3 पहले से विकसित यूएलपीजीएम-वी2 मिसाइल का उन्नत संस्करण है। यह मिसाइल तीन प्रकार के मॉड्यूलर वॉरहेड प्रदान करती है, जिसमें एंटी-आर्मर कॉन्फिगरेशन भी शामिल है, जो रोड होमोर्जीनियस आर्मर (आरएफओ) और एक्सप्लोसिव रिफ्लेक्टिव आर्मर (ईआरए) से सुसज्जित आधुनिक बख्तरबंद वाहनों की निष्क्रिय करने में सक्षम है।